पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

रामाधार सिंह

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18405

02 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के दोषमुक्ति निष्कर्षों से असहमत होने के बाद याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाकर, बिना असहमति के अनंतिम कारणों से अवगत कराए और उसे अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। (कंडिका 3, 5, 6)

हेडनोट्स

उच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी जाँच अधिकारी के दोषमुक्ति संबंधी निष्कर्षों से असहमत होने का प्रस्ताव रखता है, तो उसे अनिवार्य रूप से ऐसी असहमति के अपने संभावित कारणों को दर्ज करना होगा और दोषी कर्मचारी को उसकी एक प्रति प्रदान करनी होगी। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने और किसी भी अंतिम निर्णय से पहले प्राधिकारी को अनुकूल निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए राजी करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। (कंडिका 5, 6).

न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया अंतिम दंडात्मक आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और कानूनन टिकने योग्य नहीं है। असहमति होने पर दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करना निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। (कंडिका 5, 6, 7)

यह पुष्टि की गई कि पंजाब नेशनल बैंक बनाम कुंज बिहारी मिश्रा मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून ऐसी विभागीय कार्यवाहियों पर पूरी तरह लागू होता है। इस स्थापित कानूनी सिद्धांत के उल्लंघन में पारित कोई भी आदेश अमान्य है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। (कंडिका 5)

न्याय दृष्टान्त

पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा, (1998) 7 एससीसी 84

अधिनियमों की सूची

यह मामला विभागीय जाँचों को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमता है। किसी विशिष्ट अधिनियम का हवाला नहीं दिया गया है, लेकिन निर्णय बिहार पुलिस सेवाओं पर निष्पक्ष प्रक्रिया के संवैधानिक सिद्धांत को लागू करता है।

मुख्य शब्दों की सूची

अनुशासनात्मक कार्यवाही; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत; दूसरा कारण बताओ नोटिस; जांच रिपोर्ट से असहमति; दंड आदेश; निरस्तीकरण।

प्रकरण से उत्पन्न

पुलिस अधीक्षक, भोजपुर (उत्तरदाता सं. 4) द्वारा पारित दिनांक 30.09.2012 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सजा दी गई है, तथा उप महानिरीक्षक, शाहाबाद रेंज (उत्तरदाता सं. 3) द्वारा पारित दिनांक 17.08.2013 के अपीलीय आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपील को खारिज कर दिया गया है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री नित्यानंद मिश्रा, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/ओं के लिए: कुमारी अमृता, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: सुश्री आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 18405

रामाधार सिंह, पिता- स्वर्गीय नेमी सिंह, निवासी- गाँव-बभनौल, डाक -बभनौल, थाना-दावत, जिला-रोहतास, सासाराम। वर्तमान में सिपाही/119, रेलवे पुलिस, आरा, मुख्यालय रेलवे पुलिस, पटना के रूप में कार्यरत हैं।

... ..याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव (गृह), गृह विभाग, पुराना सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुराना सचिवालय, पटना।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, शाहाबाद रेंज, डेहरी-ऑन-सोन।
4. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, जिला- भोजपुर (आरा)।
5. पुलिस अधीक्षक, रेल पुलिस, पटना।
6. पूछताछ अधिकारी-सह-सार्जेंट मेजर, पुलिस लाइन, भोजपुर, आरा

... ..उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री नित्यानंद मिश्रा
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री कुमारी अमृता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीख:02-08-2023

1. वर्तमान रिट याचिका पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा अर्थात उत्तरदाता सं. 4 द्वारा पारित दिनांक 30.09.2012 के आदेश को निरस्त करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को 6 महीने के लिए वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया है और साथ ही, यह निर्देश दिया गया है कि याचिकाकर्ता को 123 दिनों का वेतन, अर्थात दिनांक 01.07.2011 से 31.10.2011 की अवधि का भुगतान नहीं किया जाएगा और इसके बजाय,

इसे असाधारण अवकाश के रूप में समायोजित किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने पुलिस उप महानिरीक्षक, शाहाबाद रेंज, डेहरी-ऑन-सोन अर्थात् उत्तरदाता सं-3 द्वारा पारित दिनांक 17.08.2013 के अपीलीय आदेश को निरस्त करने का भी अनुरोध किया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जब वह जिला पुलिस बल में सिपाही के पद पर कार्यरत थे, तब पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 08.06.2011 के ज्ञापन के माध्यम से आदेश जारी किया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को जिला पुलिस बल, भोजपुर, आरा से रेल जिला-पटना स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का यह मामला है कि यद्यपि दिनांक 08.06.2011 का उक्त स्थानांतरण आदेश याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया था, तथापि, कार्यमुक्त होने से पहले, उन्हें दिनांक 23.06.2011 से पीलिया होने का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप वह काम करने में असमर्थ थे, जिसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता पीलिया से पीड़ित थे और डॉक्टर द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद, उन्होंने दिनांक 23.11.2011 को पटना रेल पुलिस में कार्यभार ग्रहण कर लिया। फिर भी, पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा ने दिनांक 22.01.2012 के ज्ञापन द्वारा आरोप-पत्र जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण आदेश की अवहेलना की है, जिसके बाद याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई और एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया और फिर जाँच अधिकारी ने दिनांक 11.04.2012 की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि दोषी ने एक चिकित्सा प्रमाणपत्र और अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है और उसके अवलोकन से, यह पता चला कि याचिकाकर्ता को 01.07.2011 को कार्यमुक्त कर दिया गया था, हालाँकि, उससे पहले अपराधी को 23.06.2011 को पीलिया हो गया था, जिसके कारण वह स्थानांतरित स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका था,

लेकिन जैसे ही वह ठीक हुआ, उसने स्थानांतरित स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया, इसलिए, जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से मुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद, जाँच अधिकारी की राय से असहमत हुए बिना या कोई दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना, अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अर्थात् उत्तरदाता सं. 4 ने दिनांक 30.09.2012 को एक आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें छह महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने और अनुपस्थिति अवधि, अर्थात् 123 दिनों का वेतन जब्त करने का दंड दिया गया, हालाँकि इस अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में समायोजित करने का निर्देश भी दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता सं.3 के समक्ष अपील दायर की, हालाँकि इसे भी दिनांक 17.08.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विचारार्थ उठाया गया संक्षिप्त मुद्दा यह है कि जाँच अधिकारी ने अपनी दिनांक 11.04.2012 की जाँच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया है, हालाँकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना या ऐसी असहमति के कारणों के संबंध में अपना बचाव प्रस्तुत किए बिना, इससे असहमति जताई है और 30.09.2012 के आदेश द्वारा दंड दिया है, इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

4. इसके विपरीत, यद्यपि उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के दिनांक 30.09.2012 के दंड आदेश और दिनांक 17.08.2013 के अपीलीय आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन अभिलेखों से यह नहीं दिखा पाए हैं कि याचिकाकर्ता को कोई दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारणों के संबंध

में अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो, ताकि दिनांक 30.09.2012 के दंड आदेश को जारी करने का अधिकार प्राप्त हो सके।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि जाँच अधिकारी ने दिनांक 11.04.2012 को अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, हालाँकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना, जिसमें जाँच अधिकारी की राय से असहमति के अस्थायी कारण दर्ज किए गए थे, दिनांक 30.09.2012 को दंड का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया है। इस विषय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **पंजाब नेशनल बैंक बनाम कुंज बिहारी मिश्र, (1998) 7 एस.सी.सी. 84**, में निर्णायक रूप से तय किया गया है। इसकी कंडिका सं. 17, 19 और 21 नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

“17. ये टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से बिमल कुमार पंडित मामले [ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1612] में पहले उद्धृत टिप्पणियों के अनुरूप हैं और पहले चरण में ही लागू होंगी। उपरोक्त अंश स्पष्ट रूप से उस प्राधिकारी की आवश्यकता को उजागर करते हैं जो दोषी अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के लिए अंततः एक प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज करता है। यदि जाँच अधिकारी ने एक प्रतिकूल निष्कर्ष दिया था, तो [(1993) 4 एस.सी.सी. 727] करुणाकर मामले के अनुसार, पहले चरण में कर्मचारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक था, भले ही जाँच अधिकारी द्वारा उन्हें पहले अवसर दिया गया हो। यह तर्क नहीं होगा कि जब दोषी अधिकारियों के पक्ष में दिए गए निष्कर्ष को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पलटने का प्रस्ताव है, तो कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। जाँच

का पहला चरण तब तक पूरा नहीं होता जब तक अनुशासनात्मक प्राधिकारी अपने निष्कर्ष दर्ज नहीं कर लेता। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, जो प्राधिकारी दोषी अधिकारी के विरुद्ध निर्णय देने का प्रस्ताव रखता है, उसे उसकी सुनवाई का अवसर अवश्य देना चाहिए। जब जाँच अधिकारी आरोपों को सिद्ध करने योग्य पाता है, तो वह रिपोर्ट दोषी अधिकारी को दी जानी चाहिए, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई करने से पहले अपना पक्ष रख सकता है, जो दोषी अधिकारी के लिए हानिकारक हो सकती है। जब, वर्तमान मामले की तरह, जाँच रिपोर्ट दोषी अधिकारी के पक्ष में हो, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी ऐसे निष्कर्षों से असहमत होने का प्रस्ताव रखता हो, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध निर्णय देने वाले प्राधिकारी को उसे सुनवाई का अवसर अवश्य देना चाहिए, अन्यथा उसे बिना सुने ही दोषी ठहराया जाएगा। विभागीय कार्यवाही में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी का निष्कर्ष ही सबसे महत्वपूर्ण है।

19. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विनियम 7(2) में पढ़ा जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी आरोप के विषय पर जाँच प्राधिकारी से असहमत होता है, तो ऐसे आरोप पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, उसे ऐसी असहमति के अपने संभावित कारणों को दर्ज करना होगा और दोषी अधिकारी को अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। जाँच अधिकारी की रिपोर्ट जिसमें उसके निष्कर्ष शामिल हैं, उसे अवगत कराना होगा और दोषी अधिकारी के पास अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जाँच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए राजी करने का अवसर होगा। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, जिस प्राधिकारी को अंतिम निर्णय लेना है और जो दंड लगा सकता है, उसे कदाचार के आरोपी अधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा

उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।

21. दोनों उत्तरदाता दिनांक 31-12-1983 को सेवानिवृत्त हो गए। इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, मिश्रा की दिनांक 6-1-1995 को मृत्यु हो गई और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया। दोषी अधिकारियों को सेवानिवृत्त हुए 14 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इसलिए, यह न्याय के हित में नहीं होगा कि इस स्तर पर मामलों को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अगली पारी शुरू करने के लिए वापस भेज दिया जाए। इसलिए, हम ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं करते हैं और इन अपीलों को खारिज करते हुए, हम उच्च न्यायालय के उन निर्णयों की पुष्टि करते हैं, जिन्होंने जुर्माना लगाने वाले आदेशों को निरस्त कर दिया था और अपीलकर्ताओं को प्रतिवादियों को सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।”

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय यह पाता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के अपने अस्थायी कारणों को दर्ज न करके और याचिकाकर्ता को अपना बचाव प्रस्तुत करने और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए राजी करने का अवसर न देकर एक गंभीर गलती की है और इसके बजाय, सीधे दिनांक 30.09.2012 का दंड आदेश पारित कर दिया है, जिससे न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि यह कुंज बिहारी मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के भी विपरीत है, इसलिए दिनांक 30.09.2012 का दंड आदेश कानून की दृष्टि में दोषपूर्ण है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, उत्तरदाता सं.4 द्वारा पारित दिनांक 30.09.2012 का दंड आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है, इसलिए उसे निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, उत्तरदाता सं.3 द्वारा पारित दिनांक 17.08.2013 का अपीलीय आदेश भी असमर्थ है, इसलिए उसे भी निरस्त किया जाता है।

8. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता दिनांक 30.09.2012 के आक्षेपित आदेश और दिनांक 17.08.2013 के अपीलीय आदेश को निरस्त करने के परिणामस्वरूप सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

9. रिट याचिका की अनुमति है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

रिंकी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।